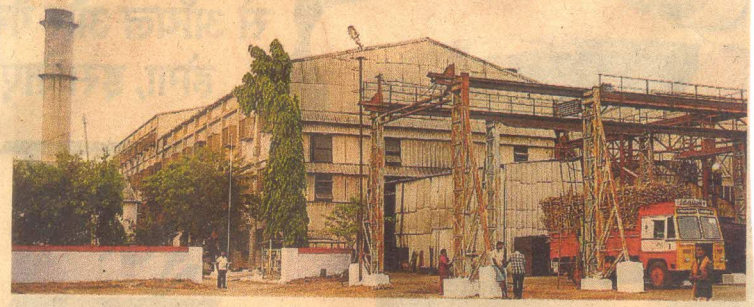

चीनी एक्सपोर्ट के मसले पर शुगर मिलों में खींचतान

[जयश्री भोसले | पुणे]

घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच किसकी चीनी का एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, इसको लेकर इंडस्ट्री की राय बंट गई है। अपना खुद का कोटा और उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का थर्ड पार्टी कोटा एक्सपोर्ट करने वाली महाराष्ट्र की शुगर मिलों का दावा है कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें समान रूप से एक्सपोर्ट में नुकसान झेले बगैर कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा उठाएंगी।

महाराष्ट्र की एक को-ऑपरेटिव चीनी मिल के मालिक ने बताया, 'हमने करीब 25 रुपये प्रति किलो के दाम पर चीनी का एक्सपोर्ट किया। घरेलू कीमतें अब बढ़कर 30 रुपये किलो के ऊपर पहुंच गई हैं। इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। अगर हमने तब शुगर का एक्सपोर्ट नहीं किया होता तो हमें इस चीनी का अच्छा दाम मिल सकता था। यूपी की चीनी मिलों को अपनी खुद की चीनी बेचने के लिए कहा जाना चाहिए। इसमें उनको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट के कारण जब दाम बढ़ेंगे तो उन्हें भी समान रूप से फायदा होगा।'

उन्होंने यह बात नाम न जाहिर करने की शर्त कही क्योंकि वह एक गवर्नमेंट स्कीम के खिलाफ बोल रहे थे। यूपी की चीनी मिलें अपना एक्सपोर्ट कोटा ट्रेडर्स को बेच देती हैं क्योंकि बंदरगाह तक उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा होती है। पिछले दो महीनों में चीनी की वायदा कीमतों में 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मौजूदा कीमतें करीब 3,250 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर हैं, जो अगस्त/सितंबर 2014 के प्राइस लेवल्स के बराबर है। चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगाड़िया का कहना है, 'चीनी की कीमतें पहले से ही हायर लेवल्स पर हैं और इन स्तरों पर इन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। प्राइसेज में करेक्शन की उम्मीद है।' महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित जिलों की चीनी मिलों ने पहले ही केंद्र सरकार से मांग की है कि उनके एक्सपोर्ट संबंधी जिम्मेदारी को घटाया जाए। उनका दावा है कि मौजूदा एक्सपोर्ट कोटा पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त स्टॉक्स नहीं हैं। केंद्र सरकार ने मिल के आधार पर कोटा तय कर दिया है, जो कि पिछले तीन सालों में प्रत्येक मिल के औसत प्रॉडक्शन का करीब 12 फीसदी है और यह पूरे देश के लिए करीब 32 लाख टन है। हालांकि, इंडस्ट्री ने मैंडेटरी शुगर एक्सपोर्ट्स की पॉलिसी लाने के लिए काफी मेहनत की। उसने पाया कि टारगेट को पूरा करना काफी मुश्किल है, जिससे सरकार को एक्सपोर्ट के लिए चीनी मिलों पर दबाव बनाना पड़ा। महाराष्ट्र को छोड़कर देश के ज्यादातर हिस्से की चीनी मिलें एक्सपोर्ट करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि, ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स की राय है कि देश के लिए टारगेट के करीब तक पहुंचना भी मुश्किल होगा।

UP की मिलों के थर्ड पार्टी कोटा एक्सपोर्ट पर महाराष्ट्र की मिलों ने जताई नाराजगी